सान्ध्य हिन्दी दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 02 | अंक - 139 | जौनपुर, बुधवार, 14 फरवरी 2024 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज - 4 | मूल्य - 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

पीएम मोदी ओल्ड गुरुग्राम में रखेंगे मेट्रो परियोजना की आधारशिला

गुरुग्राम, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को ओल्ड गुरुग्राम में नए मेट्रो रूट (मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक) की आधारशिला रखेंगे। गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री रेवाड़ी के भालखी माजरा में बनने वाले एम्स का शिलान्यास करने के साथ–साथ नए मेट्रो रूट का भी शिलान्यास करेंगे। यादव ने बताया कि अगले चार साल में 5452.72 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 28.5 किमी लंबे इस लिंक पर 27 स्टेशन होंगे। उन्होंने कहा कि ओल्ड गुरुग्राम के लोगों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ना सार्वजनिक परिवहन में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा, श्मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर पार्क तक 28.5 किलोमीटर लंबे मेट्रो रूट पर सेक्टर–45, सुभाष चौक, हीरो होंडा चौक, सेक्टर–37, सेक्टर–10, बसई, सेक्टर–4, रेजांगला चौक, पालम विहार, सेक्टर–23 समेत 27 स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बसई के पास बनने वाले मेट्रो डिपो के पास सेक्टर 101 के पास एक स्टेशन बनाकर द्वारका एक्सप्रेसवे को भी इस मेट्रो रूट से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में मेट्रो विस्तार की परियोजना के लिए राज्य सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) की तर्ज पर हरियाणा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एचएमआरसी) का गठन किया है।

आय से अधिक संपत्ति मामले में डीके शिव कुमार की बढ़ी मुश्किलें

बंगलूरू, एजेसी। आय से अधिक संपत्ति की जांच सीबीआई से अपने पास स्थानांतरित करने की उम्मीद के बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वरिष्ठ लोकायुक्त अधिकारी ने कहा कि लोकायुक्त पुलिस इस मामले को सीबीआई से लोकायुक्त को स्थानांतरित करने की उम्मीद कर रही है। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि मंजूरी वापस लेने के राज्य सरकार के आदेश पर सीबीआई ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया हुआ है। अधिकारी ने कहा कि लोकायुक्त राज्य सरकार के आदेशों को बंधा हुआ है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार हमने मामला दर्ज किया है। मामला हमें स्थानांतरित किया जाता है या नहीं। मामले की जांच करने में लोकायुक्त पर फिलहाल कोई रोक नहीं है क्योंकि अदालत ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। हालांकि, अधिकारी ने कहा कि सीबीआई द्वारा मामले के दस्तावेजों को स्थानांतरित किए बिना, कुछ बुनियादी जांच को छोड़कर हम अभी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ सार्थक जांच के लिए, हम उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार कर रहे हैं।

अन्नदाता को जेल में डालना गलत... अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की निंदा की

नई दिल्ली, एजेंसी। आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को किसानों के श्दिल्ली चलोश मार्च का समर्थन किया और कहा कि अन्नदाता को जेल में डालना गलत है। यह बयान तब आया जब आप ने कहा कि उन्होंने दिल्ली के बवाना स्टेडियम को जेल में बदलने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। केंद्र ने सोमवार को दिल्ली सरकार को 13 फरवरी को किसानों के मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों के लिए बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल के रूप में बदलने के लिए लिखा था। सरकार के अनुरोध पर आप ने कहा कि किसानों की मांगें जायज हैं और संविधान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हर नागरिक का अधिकार है। पार्टी ने कहा, किसान इस देश के अन्नदाता हैं और अन्नदाता को जेल में डालना गलत है। इस बीच, मंगलवार को किसानों के दिल्ली चलोश मार्च को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से

रोकने के लिए सीमा बिंदुओं पर मल्टी–लेयर बैरिकेड्स, कंक्रीट ब्लॉक, लोहे की कीलों और कंटेनरों की दीवारों के साथ दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। किसान नेताओं और केंद्र के बीच बातचीत बेनतीजा रहने के बाद यह बात सामने आई है। तीन सीमा बिंदुओं – सिंघू, टिकरी और गाजीपुर – पर दंगा–रोधी गियर में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को भारी संख्या में तैनात किया गया था।

कांग्रेस देगी एमएसपी की कानूनी गारंटी - राहुल गांधी

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ मिलकर एक उल्लेखनीय घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि अगर आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन सत्ता में आता है तो इंडिया ब्लॉक विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने वाला एक कानून लाएगा। गौरतलब है कि देशभर के किसानों की यह लंबे समय से लंबित मांग है। राहुल ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि किसान भाइयों आज ऐतिहासिक दिन है! कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि यह कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है। राहुल ने कहा कि आज किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं. उन्हें रोका जा रहा है, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं...वे क्या कह रहे हैं? वे सिर्फ अपने परिश्रम का फल मांग रहे हैं। बीजेपी सरकार ने एमएस स्वामीनाथन के लिए भारत रत्न की घोषणा की...लेकिन वे एमएस स्वामीनाथन की कही बात को लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि किसानों को वास्तव में एमएसपी का कानूनी अधिकार दिया जाना चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार ऐसा नहीं कर रही है...जब भारत सरकार सत्ता में आएगी, तो हम भारत के किसानों को एमएसपी की गारंटी देने वाला (कानून) देंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो कहा गया है, उसे हम पूरा करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कँटीले तार, ड्रोन से आँसू गैस, कीले और बंदूकें सबका है इंतजाम, तानाशाही मोदी सरकार ने किसानों की आवाज पर जो लगानी है लगाम ! याद है ना "आंदोलनजीवी" व "परजीवी" कहकर किया था बदनाम, और 750 किसानों की ली थी जान? 10 सालों में मोदी सरकार ने देश के अन्नदाताओं से किए गए अपने तीन वादे तोड़े हैं। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी। स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक Input Cost + 50% जीएसटी लागू करना। एमएसपी को कघनूनी दर्जा। उन्होंने कहा कि हमारा किसान आंदोलन को पूरा समर्थन है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बातचीत करके सरकार ने जो किसानों से समझौता किया था।

सीएम योगी ने जीबीसी 4.0 की तैयारियों पर की समीक्षा बैठक

लखनऊ, संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक कर आगामी 19–21 फरवरी को प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 की तैयारियों की समीक्षा की। विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विकास प्राधिकरणों के सीईओ के साथ हुई इस विशेष बैठक में मुख्यमंत्री जी ने विभागवार और जनपदवार निवेश प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए जीबीसी–4.0 के सफल आयोजन के लिए निम्न दिशा–निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में 10–12 फरवरी, 2023 को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन हुआ। इस आयोजन में 10 कन्ट्री पार्टनर, 40 देशों के 1000 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों, पार्टनर कंट्री के 04 मंत्रीगण, 17 केंद्रीय मंत्रीगणों, राजदूतों/उच्चायुक्तों और 25000 से अधिक डेलीगेट्स सहित राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों तथा अन्य गणमान्य महानुभावों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया। यह आयोजन हमारी 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं, युवाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ–साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को +1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होने वाला है। 16 देशों के 21 नगरों और देश के 10 शहरों में रोड शो सहित प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निवेशक सम्मेलन के उपरांत तीन दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से रू39.52 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इससे 1.10 करोड़ नौकरीध रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अब उत्तर प्रदेश इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आगामी 19–21 फरवरी तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में तीन दिवसीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन होने जा रहा है। पहले दिन 19 फरवरी को प्रधानमंत्री जी द्वारा एक साथ रू10 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों के जमीनी क्रियान्वयन की शुरुआत होगी। इस अवसर पर उद्योग जगत के अनेक प्रतिष्ठित समूह, सीईओ, निवेशकों आदि की गरिमामयी उपस्थिति होगी। देश के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश का यह समारोह प्रदेश के

साथ–साथ पूरे देश के औद्योगिक विकास को गति देने का माध्यम होगा। ऐसे में समारोह की गरिमा और महत्ता के दृष्टिगत सभी आवश्यक प्रबन्ध कर लिए जाएं। वर्ष 2018 में इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन के बाद जब पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित हुई थी, रू60 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों का क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ था। आज 06 वर्ष बाद जीबीसी/आईटी में एक साथ रू10 लाख 11 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों के ग्राउंड ब्रेकिंग की तैयारी है। यह ट्रांसफॉर्मेशन, यह बदलाव, यही स्पीड नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। जीबीसी/आईटी में रू500 करोड़ से अधिक की 262 परियोजनाएं सम्मिलित हैं, जबकि रू100–500 करोड़ तक 889 औद्योगिक परियोजनाएँ जमीन पर उतरेंगी। महत्वपूर्ण यह भी कि सभी 75 जनपद इससे लाभान्वित होंगे। 3500 से अधिक इन्वेस्टर्स इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। विशिष्ट समारोह में अनेक केंद्रीय मंत्रीगणों, विभिन्न राजदूतों, जनप्रतिनिधिगणों की सहभागिता भी होनी है। अति विशिष्ट जनों के सुरक्षा व सत्कार प्रोटोकाल का पूर्णतः अनुपालन किया जाना चाहिए। सीएम फेलो की काउंसिलिंग/ट्रेनिंग करके उन्हें इन अतिविशिष्ट जनों के साथ संबद्ध किया जाए। औद्योगिक जगत के शीर्षस्थ जनों, उद्यमियों, निवेशकों आदि गणमान्य जनों की आवासीय व्यवस्था, भोजन, आवागमन, पार्किंग आदि के समुचित प्रबंध किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पूर्व सेवानिवृत्त आईएएसध्आईपीएसध्आईएफएस अधिकारियों, कुलपतिगणों के सहयोग से विभिन्न विश्व विद्यालयों/कॉलेजों में युवाओं के साथ इन्वेस्टर्स समिट की उपयोगिता, महत्ता, प्रभाव के बारे में संवाद का अभिनव प्रयास किया

सीएसआर स्थानीय बोली में सामग्री प्रसारित करने के लिए मंच प्रदान करता है – अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली, एजेंसी। सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन

(सीआरएस) स्थानीय बोली में सामग्री प्रसारित करने के लिए बहुत जरूरी मंच प्रदान करता है। क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन (दक्षिण) के दौरान विश्ध्व रेडियो दिवस के अवसर पर अन्ना विश्वविद्यालय में एक समारोह को वर्चुअल तौर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सामुदायिक रेडियो स्टेशन एक मंच प्रदान करते हैं, जहां सामग्री स्थानीय बोलियों और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित की जाती है। उन्होंने कहा कि इन स्टेशनों पर स्थानीय मुहावरों में स्थानीय मुद्दे उठाए जाते हैं और उन पर चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा, "सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में सामुदायिक रेडियो को समझना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि रेडियो कितना महत्वपूर्ण है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि हमें यह देखना चाहिए कि पीएम मोदी अपने श्मन की बातश कार्यक्रम में कैसे उदाहरण पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय सम्मेलन सीआरएस समुदाय को करीब लाने के लिए एक आदर्श मंच हैं। उन्होंने कहा, जो संस्थान कई जिलों में काम करते हैं, उन्हें संचालन के विभिन्न जिलों में अधिकतम 6 सीआरएस स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।

लोक परीक्षा से जुड़े विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

नई दिल्ली, एजेसी। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए कुछ दिन पहले बजट सत्र में संसद द्वारा लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक–2024 को पारित किया गया था, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि इस कानून का उद्देश्य तमाम सरकारी प्रवेश परीक्षाओं में धांधली रोकना है और धोखाधड़ी की जांच करना है। साथ ही सरकारी परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना है। गौरतलब है कि सोमवार को राष्ट्रपति ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। यह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा तय की गई तारीख पर लागू होगा। अधिनियम में सार्वजनिक परीक्षाओं का अर्थ केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं से है। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान और भर्ती के लिए केंद्र सरकार के विभाग और उनसे जुड़े कार्यालय शामिल हैं। सार्वजनिक परीक्षा के दौरान

उम्मीदवार की सहायता करना, कंप्यूटर नेटवर्क या संसाधनों के साथ छेड़छाड़ करना, शॉर्टलिस्टिंग या मेरिट सूची या रैंक को अंतिम रूप देने के लिए दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना और फर्जी परीक्षा के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। यह अधिनियम समय से पहले परीक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी का खुलासा करने और अनधिकृत लोगों को व्यवधान पैदा करने के लिए परीक्षा केंद्रों में प्रवेश करने से भी रोकता है। इन अपराधों के लिए तीन से पांच साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा।

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में प्रश्नपत्र लीक होने के मामलों ने लाखों छात्रों और अभ्यर्थियों के हितों को प्रभावित किया है। इसे रोकना जरूरी है। ऐसा नहीं करना लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। बजट सत्र की शुरुआत पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंताओं से अवगत है।

इस दिशा में सख्ती लाने के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया गया है। विधेयक का मकसद परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकना है। संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान और केंद्र सरकार के विभाग और भर्ती के लिए उनके जुड़े कार्यालय द्वारा कराई जाने वाली परीक्षाएं इस विधेयक के दायरे में आएंगी।

तेलंगाना लोकसभा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस के बीच होगी सीधी टक्कर - किशन रेड्डी

हैदराबाद, एजेंसी। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने रविवार को भविष्यवाणी की कि राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होगी। 20 फरवरी से शुरू होने वाली भाजपा विजय संकल्प यात्रा के संबंध में पोस्टर जारी करने वाले किशन रेड्डी ने दावा किया कि देशभर के सभी लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा के पक्ष में माहौल है और लोगों ने पहले ही आगामी चुनावों में कमल को वोट देने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के युवा चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनें। उन्होंने घोषणा की कि तेलंगाना के लोगों का समर्थन और आशीर्वाद पाने के लिए पांच संसद क्षेत्रों में पांच यात्राएं आयोजित की जाएंगी। ये यात्राएं 20 फरवरी से 1 मार्च तक होंगी। यात्राओं को क्लस्टर

अनुसार नाम दिए गए हैं। भुवनगिरि, मल्काजगिरि, सिकंदराबाद और हैदराबाद संसदीय क्षेत्रों के लिए यात्रा को भाग्यनगर कहा जाएगा। करीमनगर, मेडक, जहीराबाद और चेवेल्ला निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करने वाली यात्रा को सातवाहन नाम दिया गया है। इसी तरह, आदिलाबाद, पेद्दापल्ली और निजामाबाद निर्वाचन क्षेत्रों में यात्रा को कुमारम भीम यात्रा के नाम से जाना जाएगा। किशन रेड्डी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अभी तक देश में कहीं भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा कि भाजपा की राज्य चुनाव समिति और चुनाव प्रबंधन समिति चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए सोमवार को बैठक करेगी। कालेश्वरम परियोजना के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने अतीत में मेदिगड्डा बैराज का दौरा किया था और उन्हें एक बार फिर वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कृष्णा नदी जल बंटवारे का विवाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच बातचीत से सुलझाया जा सकता है।

सीएम एन बीरेन सिंह का बड़ा बयान, 1961 के बाद मणिपुर में बसने वालों को निकालेंगे बाहर

मणिपुर, एजेंसी। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को कहा कि 1961 के बाद राज्य में आने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान की जाएगी और उसे निर्वासित किया जाएगा, चाहे वह किसी भी जाति या समुदाय का हो। आपको बता दें कि पड़ोसी देशों से चिन कुकी जनजाति के अवैध अप्रवासी भी राज्य में उचित दस्तावेजों के बिना रह रहे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जारी एक बयान में, बीरेन सिंह ने कहा कि 1961 के बाद दुनिया के अन्य हिस्सों से राज्य में आने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान की जाएगी और उसे निर्वासित किया जाएगा। सीएम सिंह ने कहा कि मणिपुर की मूल आबादी का पता लगाने और अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए जनसंख्या आयोग का गठन किया गया है। जनसंख्या आयोग के सदस्य आईएलपी और 1961 को आधार वर्ष मानकर घर–घर जाकर जनसंख्या सर्वेक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि जनसंख्या की दो श्रेणियां होंगी–स्वदेशी और स्थायी निवासी। जो लोग 1961 से पहले मणिपुर आए, उन्हें स्थायी निवासी माना जाएगा। जो लोग 1961 के बाद आये, उन्हें स्थायी निवासी नहीं माना जायेगा। राज्य सरकार ने राज्य में विभिन्न परमिटों को पंजीकृत करने, डेटा संग्रह, ट्रैकिंग और आईएलपी की निगरानी के लिए आईएलपी पोर्टल भी लॉन्च किया। आईएलपी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो राज्य सरकार द्वारा एक विशिष्ट अवधि के लिए मणिपुर जाने वाले भारतीय नागरिक की आंतरिक यात्रा की अनुमति देने के लिए जारी किया जाता है। एन बीरेन सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में पोस्त की अवैध खेती को खत्म करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सचिवालय में बृहस्पतिवार को इस खतरे को खत्म करने के उपायों और नई रणनीतियों पर विचार–विमर्श के लिए एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

संपादकीय

पाक में अप्रत्याशित वसंत

राष्ट्रों को चुनावों में अस्पष्ट फैसले देने के लिए जाना जाता है, जिससे त्रिशंकु विधायिकाएं बनती हैं और गठबंधन की स्थिति बनती है। हालाँकि, पाकिस्तान उन देशों में से एक है जहाँ इस तरह के फैसले देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं क्योंकि ऐसी स्थितियों को लाने में कई बाहरी कारक भूमिका निभाते हैं। पाकिस्तान में हाल ही में हुए आम चुनाव में खंडित जनादेश ने राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक व्यवहार्यता और राष्ट्र की अस्तित्वगत स्थिति की समस्याएं पैदा कर दी हैं। इसके चलते पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा (केपीके), बलूचिस्तान और सिंध में प्रांतीय चुनावों में चार अलग–अलग पार्टियों ने प्रमुख स्थान हासिल कर लिया है। नेशनल असेंबली का निचला सदन, जो राष्ट्रीय सरकार के गठन का फैसला करता है, और भी बदतर है। सेना समर्थक पार्टियाँ दृ पीएमएल (एन) और पीपीपी दृ जिन्होंने पहले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) का गठन किया था, ने 265–मजबूत संसद में क्रमशः 76 और 54 रन बनाए हैं, जिसके लिए 134 सीटों वाले एक समूह या एकल पार्टी की आवश्यकता होती है। सरकार बनाओ. पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेट आइकन इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक–ए–इंसाफ (पीटीआई), जिसे उसके चुनावी चिह्न (क्रिकेट बैट) पर प्रतिबंध के कारण भाग लेने से रोक दिया गया था, 97 स्वतंत्र उम्मीदवारों को निर्वाचित कराने में कामयाब रही दृ माना जाता है कि सभी पीटीआई द्वारा समर्थित थे। फिर केंद्र में सरकार कौन बनाता है यह एक मिलियन डॉलर का सवाल है क्योंकि हमने अभी तक कमरे में हाथी का उल्लेख नहीं किया है दृ पाकिस्तानी सेना, जो स्वीकार्य व्यक्तित्वों के नेतृत्व में शासन करने के लिए गठबंधन बनाने के लिए अंतिम प्राधिकारी बनी हुई है। यह सिर्फ एक नेता नहीं है बल्कि ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सेना द्वारा स्वीकार्यता का प्रमाण है। स्थिति की जटिलता को समझने के लिए, उन कारकों के बारे में जागरूक होना होगा जो यहां प्रभाव डाल रहे हैं और अंततः यह तय करना होगा कि देश किस दिशा में जाएगा। पीटीआई की वैधता कानूनी कारकों के कारण संदिग्ध है और 97 निर्दलीय विधायकों को बनाए रखने की इसकी क्षमता भी संदिग्ध है। हालाँकि, इसकी अपील वास्तविक है और यह उन युवाओं के लिए है जिन्होंने स्पष्ट रूप से पीटीआई के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवारों को वोट दिया है। सामान्य परिस्थितियों में, यह वोट आगे बढ़ता और केंद्र में सही स्थिरता पैदा करता, लेकिन पीटीआई के नेता इमरान खान बिल्कुल सेना के पसंदीदा नहीं हैं। छह साल पहले एक समय, वह था। हालाँकि, अधिक स्वतंत्र रक्षा और विदेश नीति का पालन करने का प्रयास करते समय वह तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा के साथ भाग गए, जिसमें डीजी आईएसआई जैसी प्रमुख नियुक्तियों में विभिन्न जनरलों की नियुक्ति शामिल थी। इमरान खान के खिलाफ व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए गए थे, जिसकी जांच का नेतृत्व वर्तमान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर कर रहे थे। अंततः इमरान खान को संवैधानिक रूप से हटा दिया गया और एक गठबंधन बनाया गया जिसने लगभग 15 महीने तक पाकिस्तान पर शासन किया। जब तक पीटीआई को बाहर रखा गया और सेना द्वारा प्रताड़ित किया गया, तब तक गठबंधन में किसी ने भी घटक दलों की वैयक्तिकता पर जोर देने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब यह अलग होने जा रहा है. अगली सरकार अंतरिम नहीं है, यह पांच साल के लिए है, और इसलिए घटकों के बीच सत्ता का खेल जैसे मतभेद लाने वाले कारकों से मुकाबला करना होगा। इस चुनाव, या "चयन", जैसा कि अक्सर कहा जाता है, और इसके परिणामों में, पाकिस्तानी सेना द्वारा अनौपचारिक रूप से कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ शर्तें निर्धारित की गई थीं। सबसे पहले इमरान खान और उनकी पीटीआई को सत्ता में आने की किसी भी संभावना से बाहर करने की आवश्यकता थी। दूसरा, पीपीपी या पीएमएल (एन) जैसी मुख्यधारा की पार्टियों में से किसी एक पार्टी का सत्ता में आना टाला जा सकता था क्योंकि इससे मतभेद के मुद्दे उठने पर सेना के साथ टकराव की संभावना बढ़ जाती। फिर भी, पाकिस्तान की लगभग ढह चुकी अर्थव्यवस्था के लिए कोई आर्थिक राहत पाने के लिए एक स्थिर मोर्चे का अनुमान लगाना आवश्यक था। वाशिंगटन की अपनी यात्रा के दौरान अमेरिकी अधिकारियों के साथ अपने लंबे विचार–विमर्श में, जनरल असीम मुनीर ने संभवतः अपनी रणनीति के लिए समर्थन लिया और चरमपंथी तत्वों को बाहर करने पर भी काम करने का वादा किया ताकि उन्हें कट्टरपंथी वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कोई आधिकारिक नियंत्रण न मिले। अमेरिका के लिए, जो अफगानिस्तान में तालिबान को जीवित रहने में गुप्त रूप से मदद कर रहा है, प्रायोजित प्रॉक्सी तहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के माध्यम से पाकिस्तान में अफगान तालिबान के एजेंडे को आगे बढ़ाना अनुत्पादक होगा। जनरल मुनीर के लिए, उनका एजेंडा ऐसी चुनावी स्थिति हासिल करना था, जिससे वह भू–राजनीतिक एजेंडे के बजाय भू–आर्थिक एजेंडे का पालन करने का आग्रह कर सकें। तथाकथित मुनीर सिद्धांत के हिस्से के रूप में, जो उनकी सोच के लिए जिम्मेदार है, उनका इरादा रणनीतिक तटस्थता के एजेंडे के बाद पाकिस्तान को एक स्थिर क्षेत्रीय सुरक्षा अभिनेता में बदलना था। कई मायनों में, पाकिस्तानी सेना ने अपने समग्र एजेंडे का कम से कम कुछ हिस्सा हासिल कर लिया है। हालाँकि, "चयन" को संभालने में काफी लापरवाही बरती गई है, जिससे खुद को वैधता के आरोपों पर निशाना बनाया जा सकता है। यह केवल उस पर अमल करने के बजाय इंटरनेट शटडाउन और अन्य नियंत्रण उपायों के बारे में आधिकारिक तौर पर चेतावनी दे सकता था और फिर इसे आतंकवादी खतरों के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता था।

मोदी की कूटनीति से धमाकेदार जीत संभव

ललित

2024 के आम चुनावों का रण सज चुका है, कुछ ही हफ्ते बचे हैं और भारतीय जनता पार्टी एवं सभी विपक्षी दलों ने भी कमर कस ली है। भाजपा एवं इंडिया गठबंधन दोनों ही खेमों में अब हर दिन चुनावी रणनीति को लेकर बैठकों, मुलाकातों एवं चुनावी गणित को फीट करने का दौर चल रहा है, एक तरफ भाजपा 2 हफ्ते बाद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मकर संक्रांति के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल करने वाला है, लेकिन भाजपा ने स्वयं 370 एवं उसके गठबंधन का 400 का लक्ष्य लेकर ही चल रही है। हाल ही में एक मीडिया हाउस के सर्वे के अनुसार भाजपा को भले ही 2019 की तुलना में केवल एक सीट का फायदा हो रहा है, भले नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है लेकिन उनके गठबंधन को करीब 17 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है अन्य माध्यमों से भी ऐसी ही सूचनाएं भाजपा को मिल रही हो, इसलिये उसने 400 के लक्ष्य को हासिल करने का ठाना है। भाजपा एवं मोदी की चुनावी रणनीतियों एवं विश्वास से ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर धमाकेदार जीत दर्ज कर अपनी हैट्रिक पूरी करेगी। इस जीत के बाद भारत में बड़े बदलाव एवं क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। राजनीति, प्रशासनिक, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आमूल–चूल परिवर्तन हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। नरेन्द्र मोदी, उनके राजनीतिक सलाहकार एवं भाजपा सम्भवतः इस मोड पर पहुंच गए हैं कि चुनाव जीतने के लिए उन्हें जितने तरह का रणनीतिक प्रबंधन करने जरूरी थे, वे सफलतापूर्वक किये जा चुके हैं या जल्द ही कामयाबी से कर लिये जाएंगे। जितनी कमजोर कड़ियां थीं, उनकी मरम्मत कर ली गई है। जिन राज्यों में खराब दृश्य दिख रहे हैं, वहां भाजपा पूरी ताकत से लगी है। भाजपा ने 164 ऐसी सीटों की दो कैटेगरी तैयार कर ली है जहां 45 मंत्रियों को जी–जान से जुटने को कहा गया है, भाजपा कमजोर सीटों पर सबसे ज्यादा जोर लगा रही है क्योंकि 2019 के चुनाव में भाजपा की 48 ऐसी सीटें थीं जहां जीत का अंतर 2 प्रतिशत से भी कम था, इन सीटों पर विपक्षी गठबंधन अगर एक उम्मीदवार उतार देता है तो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। ऐसी ही खतरे वाली सीटों के लिये भाजपा की तीक्ष्ण एवं प्रभावी रणनीतियां बन रही है। ऐसी ही रणनीतियां से समूचे राष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्यों को बदलने एवं अपने पक्ष में करने के लिये भाजपा जुटी है। इसके लिये प्रभावी एवं दूरगामी राजनीतिक से जुड़े बड़े फैसले लिये जा रहे हैं। नीतीश कुमार और जयंत चौधरी जैसे नेताओं को इंडिया गठबंधन से छीन लिया गया है। कांग्रेस के अशोक चव्हान को भाजपा में शामिल करके राज्यसभा में भेजा जा रहा है। मायावती और चंद्रबाबू नायडू को विपक्ष में जाने से रोक दिया गया है। शिवसेना और राकांपा की दो फाड कर दी गयी है। श्रीराम मन्दिर उद्घाटन से हिन्दू वोटों को प्रभावित किया गया है, वही पांच राजनीतिक रत्नों को 'भारत रत्न' सर्वोच्च पुरस्कार की घोषणा से आम चुनावों को प्रभावित करने का राजनीतिक कौशल दिखाया गया है। जब इतना बढ़िया, कौशलपूर्ण और प्रभावी राजनीतिक प्रबंधन हो चुका हो तो चार सौ का लक्ष्य हासिल करना भाजपा के लिये असंभव प्रतीत नहीं होता। वैसे प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता नरेन्द्र मोदी को ही सर्वाधिक पसन्द कर रही है, एक अनुशासित एवं राष्ट्रीय मूल्यों से प्रेरित पार्टी के रूप में भाजपा कायम है। मोदी का राजनीतिक कौशल ही है कि आम तौर से सरकारें चुनाव से पहले अपना खजाना खोलती हैं, लेकिन मोदी बिना खजाना खोले एवं लोकलुभावना घोषणाओं के चुनावी वैतरणी को सफलतापूर्वक पार करने की रणनीति बना रही है। मोदी जानते हैं कि लोकलुभावन योजनाएं या लाभार्थियों का संसार अपने आप वोटों में नहीं बदलता। उसके तीन स्तरों पर काम करना होता है। राज्यों के स्तर पर जहां अपनी स्थिति लगातार मजबूत करना जरूरी होता है, नेताओं के स्तर पर जो विभिन्न समुदायों की नुमाइंदगी करते हैं और समुदायों के स्तर पर जिन्हें लगातार पार्टी के साथ जोड़ने का अभियान चलाना पड़ता है। एक और स्तर इस बार के चुनावी गणित को प्रभावित करती हुई प्रतीत हो रही है, वह है मोदी का राजनीतिक कौशल एवं देश–विकास का उनका संकल्प। निश्चित ही मोदी भारतीय राजनीति में विश्वास और विकास के नायक हैं तो वैश्विक पटल पर महानायक बनकर देश और दुनिया को दिशा दिखा रहे हैं। कतर की जेल में बंद आठ पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई और उनमें से सात का स्वदेश आ जाना एक ऐसी शुभ सूचना है, जिससे पूरे देश ने चौन की सांस ली है।

ईपीएफ में न्यूनतम पेंशन का सवाल

अश्वनी महाजन

एंप्लाइज पेंशन स्कीम (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत, ऐसे कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्य हैं, उनके लिए न्यूनतम पेंशन का प्रावधान पहली बार भारत सरकार द्वारा 1995 में किया गया था, जिसे 2014 में 1000 रुपए प्रतिमाह तक बढ़ा दिया गया, लेकिन कर्मचारी पिछले कुछ समय से मूल पेंशन में वृद्धि करने और अन्य मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। सभी के लिए ज्यादा पेंशन रू ईपीएस स्कीम के तहत अभी सभी कर्मचारियों के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन का प्रावधान है। लेकिन मजदूर संगठनों द्वारा बार–बार यह मांग की जा रही है कि सभी सदस्यों को ज्यादा पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। अलग–अलग संगठनों ने इसके लिए अलग–अलग पेंशन राशि की मांग की है। इस संबंध में, देश के सबसे बड़े मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ की मांग है कि सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और पेंशन अंतिम आहरित वेतन का आधा तय किया जाना चाहिए, और ईपीएस कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। अलग–अलग प्रकार की पेंशन रू गौरतलब है कि देश में कर्मचारियों के लिए उनके नियोक्ता के हिसाब से अलग–अलग प्रकार की सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का प्रावधान है। एक तरफ 2004 से पूर्व में नियुक्त सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्हें सरकार उनकी पूरी सेवा अवधि के बाद आखिरी वेतन के आधे के बराबर मासिक पेंशन के रूप में प्रदान करती है। 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम का प्रावधान है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा भविष्य निधि में योगदान दिया जाता है, जिसे नई पेंशन स्कीम के नियमों के अनुसार प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है, और उसी संचित निधि में से योगदान पर आधारित पेंशन देने का प्रावधान है। नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारी भी लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की मांग कर रहे हैं और कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली भी कर दी है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी ईपीएफओ के अंतर्गत आते हैं। ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा राशि ईपीएफओ में जमा की जाती है और इस प्रकार से हर कर्मचारी द्वारा जमा कुल राशि पर हर साल घोषित ब्याज दर के हिसाब से ब्याज लगाया जाता है। अपने सेवा काल के दौरान जमा की गई राशि और साथ ही ब्याज पर भुगतान सेवानिवृत्ति अथवा नौकरी छोडने या छूटने पर कर्मचारी को कर दिया जाता है। वर्ष 1995 से ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को उनकी जमा राशि और ब्याज के अलावा न्यूनतम पेंशन का प्रावधान किया गया और उसे बाद में 1000 रुपए प्रतिमाह तक बढ़ाया गया। इसके बाद कर्मचारियों की लगातार यह मांग रही है कि यह राशि अत्यंत कम है और इसमें वृद्धि होनी चाहिए। यही नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा गैर ईपीएफओ कर्मचारियों और मजदूरों एवं स्वरोजगार युक्त छोटे व्यापारियों के लिए नई शुरुआत की गई है। गैर ईपीएफओ कर्मचारियों और मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–धन योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना प्रारंभ की गई है एवं व्यापारी और स्वरोजगार युक्त व्यक्तियों के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। इन दोनों योजनाओं में 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 55 रुपए से 200 रुपए प्रति माह तक मासिक योगदान करना होगा। एक बार जब लाभार्थी 18–40 वर्ष की प्रवेश आयु में योजना में शामिल हो जाता है, तो लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक योगदान करना होता है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ग्राहक को, जैसा भी मामला हो, पारिवारिक पेंशन के लाभ के साथ 3000 रुपए की सुनिश्चित मासिक पेंशन डीबीटी द्वारा प्राप्त होगी। यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी ग्राहक ने लगातार योगदान का भुगतान नहीं किया है, तो उसे सरकार द्वारा तय किए गए दंड शुल्क, यदि कोई हो, के साथ–साथ संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करके अपने योगदान को नियमित करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त सरकारी बैंकों और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में सामाजिक सुरक्षा की अलग–अलग व्यवस्था है। यानी कहा जा सकता है कि देश हर कम या ज्यादा सभी आय वर्गों के कर्मचारी और स्वरोजगार युक्त व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न प्रकार की रचना देश में बनी हुई है। गौरतलब है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और स्वरोजगार युक्त लोगों को दी जाने वाली पेंशन का भुगतान मोटे तौर पर तब करना होगा जब वर्तमान में इसके लिए जिन 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों ने सदस्यता ली है। यानी इस योजना के लिए राशि का प्रावधान कम से कम 20 वर्ष से पहले नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि ईपीएफओ के सदस्यों को यदि ऊंची पेंशन देनी पड़े तो उसकी देनदारी तुरंत ही ईपीएफओ के संचित फंड पर पड़ेगी और इतनी पेंशन देने के बाद ईपीएफओ की संचित राशि धीरे–धीरे समाप्त हो सकती है। ऐसे में ईपीएफओ में अपना योगदान देने वाले कर्मचारियों को भविष्य में उनकी राशि वापस करने में कठिनाई हो सकती है।

लाजिस्टिक लागत घटने का परिदृश्य

आदित्य

इन दिनों राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत में लॉजिस्टिक लागत घटने से संबंधित जो अध्ययन रिपोर्टें प्रकाशित हो रही हैं, उनके आधार पर भारत में वर्ष 2024 में विनिर्माण, कारोबार, निर्यात और रोजगार के मौके बढ़ाने में घटती हुई लॉजिस्टिक लागत की अहम भूमिका होगी। हाल ही में उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने 'भारत में लॉजिस्टिक्स लागत रू आकलन और दीर्घावधि फ्रेमवर्क' रिपोर्ट 2023 को जारी करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2021–22 में भारत की लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 7.8 से 8.9 प्रतिशत के बीच रही है। इस लघॅजिस्टिक लागत में यातायात लागत, वेयर हाउसिंग और भंडारण लागत, सहायक सहायता सेवाओं की लागत, पैकेजिंग की लागत, बीमा लागत और अन्य संचालन लागतें शामिल की गई हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकानॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) द्वारा विश्व बैंक के निर्धारित मापदंडों पर तैयार की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट तथा यातायात के साधनों में बड़े निवेश और आधुनिकीकरण जैसे अहम कारणों से लॉजिस्टिक लागत में बड़घी कमी आई है। उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 के तहत भी भारत 6 पायदान की छलांग के साथ 139 देशों की सूची में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत 2018 में इस सूचकांक में 44वें तथा 2014 में 54वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जिस रणनीतिक रूप से पीएम गति शक्ति योजना 2021 और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) 2022 का कार्यान्वयन शुरू किया गया है, उससे भारत में लॉजिस्टिक लागत में कमी का परिदृश्य लगातार उभरकर दिखाई देने लगा है। ज्ञातव्य है कि सामान्यतः वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल की लागत पहले क्रम पर और मजदूरी की लागत दूसरे क्रम पर होती है। फिर लॉजिस्टिक लागत का क्रम आता है। उत्पादों एवं वस्तुओं को उत्पादित स्थान से गंतव्य स्थान तक पहुंचाने तक लगने वाले परिवहन, भंडारण व अन्य खर्च को लॉजिस्टिक खर्च कहा जाता है। जहां डीपीआईआईटी के द्वारा हाल ही में प्रस्तुत रिपोर्ट में लॉजिस्टिक लागत नौ फीसदी से भी कम रहने की बात कही गई है, वहीं लॉजिस्टिक से जुड़े कई संगठनों की अध्ययन रिपोर्टों में भारत में लॉजिस्टिक की लागत जीडीपी के 10 फीसदी से अधिक होने के अनुमान भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वस्तुतरू कोई एक वर्ष पहले 17 सितंबर 2022 को लांच हुई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी का लक्ष्य पांच साल में देश में लॉजिस्टिक लागत को घटाकर 8 फीसदी करना है। साथ ही इसका लक्ष्य 2030 तक कम लॉजिस्टिक खर्च वाले दुनिया के टॉप 25 देशों की सूची में देश को भी कम लॉजिस्टिक लागत वाले देश के रूप में स्थान दिला पाना भी है। इसका लक्ष्य माल परिवहन की लागत घटाकर सभी प्रकार के उद्योग–कारोबार को बढ़ावा देना और वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना भी है। चूंकि वर्तमान में लॉजिस्टिक्स का ज्यादातर काम सडकों के जरिए होता है, अतएव अब इस नीति के तहत रेल ट्रांसपोर्ट के साथ–साथ शिपिंग और एयर ट्रांसपोर्ट पर जोर दिया जा रहा है। लगभग 50 प्रतिशत कार्गो को रेलवे के जरिए भेजे जाने का लक्ष्य आगे बढ़ाया जा रहा है और सडकों पर ट्रैफिक को कम किया जा रहा है। देश में बुनियादी ढांचे का तेजी से निर्माण होने लगा है। साथ ही लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ड्रोन का भी इस्तेमाल शुरू हुआ है। निरूसंदेह नई लॉजिस्टिक नीति और करीब 100 लाख करोड़ रुपए की महत्त्वाकांक्षी पीएम गतिशक्ति योजना एक सिक्के के दो पहलू की तरह ही हैं। गति शक्ति योजना का मुख्य लक्ष्य देश में एकीकृत रूप से बुनियादी ढांचे का विकास करना है। वस्तुतरू देश में सडक, रेल, जलमार्ग आदि के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 16 मंत्रालयों और विभागों के बीच पीएम गतिशक्ति योजना के तहत सहकार व समन्वय बनाने का काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। गतिशक्ति योजना के तहत पिछले दो वर्षों में विभिन्न विभागों की अवसंरचना विकास से जुड़ी गतिविधियों को एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल के तहत लाए जाने का काम हुआ है। साथ ही अब रेलवे, सडक, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, सार्वजनिक परिवहन और लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में चिन्हित किए गए सात इंजनों के तहत भारतमाला (राजमार्ग), सागरमाला (तटीय नौवहन), उड़ान (वायु सेवाओं), भारत नेट (दूरसंचार सेवाओं), रेलवे विस्तार और अंतर्देशीय जलमार्ग विस्तार जैसी महत्त्वपूर्ण योजनाओं को समन्वित रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। वस्तुतरू इस समय केंद्र सरकार सडक और रेल मार्ग, दोनों में सुधार पर ध्यान दे रही है। देश के प्रमुख शहरों और औद्योगिक एवं कारोबारी केंद्रों के बीच की दूरी कम करने के लिए एक तरफ डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के जरिए रेल मार्ग से माल ढुलाई को तेज करने की कवायद कर रही है, दूसरी तरफ देश के लगभग हर हिस्से में ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके साथ ही राजमार्गों पर आधारित इंडस्ट्रियल कोरिडोर भी बनाए जा रहे हैं। यह बात भी उभरकर दिखाई दे रही है कि देश में बुनियादी ढांचे के तहत सडकों, रेलवे, बिजली और हवाई अड्डों के अलावा बंदरगाह से संबंधित सडक और रेल कनेक्टिविटी में भी निजी निवेश का प्रवाह अहम भूमिका निभा रहा है। यात्रा के आधार पर भारत का लगभग 90 फीसदी से अधिक विदेश व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। देश में नवीनतम बंदरगाह नीति के तहत बंदरगाह 'लैंडलॉर्ड मॉडल' की शुरुआत के साथ सरकार के स्वामित्व वाले प्रमुख बंदरगाह की परिचालन जिम्मेदारियां निजी क्षेत्र को सौंपने की रणनीति के कारण बंदरगाह विकास और संचालन में घरेलू और विदेशी निजी क्षेत्र की भागीदारी तेजी से बढ़ी है।

राजनीति में रंगे भारत रत्न की कहानी

राजेंद्र

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पांच भारत रत्न पुरस्कारों की घोषणा देशभर में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसलिए कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के नेपथ्य में छिपी मंशा या एजेंडे को देश का अनपढ़ मतदाता भी बखूबी समझ रहा है। एक ऐसा पुरस्कार जो 1954 में अपनी स्थापना से लेकर अब तक गरिमा, गौरव और प्रतिष्ठा का प्रतीक रहा है, का राजनीतिक मन्सूबों के लिए इस्तेमाल शायद पहले कभी बड़े स्तर पर नहीं हुआ। कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवानी, चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम.एस. स्वामिनाथन को भारत रत्न से विभूषित किए जाने की आलोचना इसलिए हो रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इन्हें 'ट्रम्प कार्ड' के रूप में प्रयोग कर चुनावी समीकरण, गठबन्धन साधना चाहती है, ताकि तीसरी बार वह सत्तासीन हो सके। धारा 370 हटाने से लेकर राम मन्दिर के निर्माण आदि में जो कामयाबी, लोकप्रियता भाजपा ने हासिल की है, उससे देशभर में यह माहौल बनाया जा चुका है कि तीसरी दफा भाजपा की विजय निश्चित है। गोदी मीडिया तो अपने सर्वे में भाजपा को जिता ही चुका है। ऐसे में भारत रत्न को हथियार बनाकर लोकसभा में 400 का आंकड़ा पार करने की शायद जरूरत नहीं थी। लेकिन साम, दाम, दण्ड, भेद से चुनाव जीतना ही एकमात्र लक्ष्य है। कर्पूरी ठाकुर बिहार में हाशिए पर सिमटे लोगों यानी दलित पिछड़ों की आवाज थे। लेकिन यह पुरस्कार उन्हें ऐसे वक्त मिला है जब 'पलटू राम' सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा के पाले में पुनरू लुढकने के लिए तैयार बैठे थे। कर्पूरी ठाकुर निश्चित रूप से इस पुरस्कार के हकदार हैं, पर यह उन्हें कई दशक पहले मिल जाना चाहिए था। लालकृष्ण आडवानी को हिन्दुत्व के एजेन्डे को बढ़ावा देने के लिए भारत रत्न मिला। राम मन्दिर की प्राण प्रतिष्ठा से चन्द रोज बाद। लेकिन जानकार भूले नहीं हैं कि रामरथ यात्रा मंडल कमीशन द्वारा ओबीसी तबके को आरक्षण देने के जवाब में आरम्भ हुई थी। देशभर में जिस–जिस शहर से आडवाणी की यात्रा गुजरी थे, दंगे हुए। बेकसूर लोग मौत के घाट उतारे गए। आडवाणी का देश को एक सूत्र में जोडने, भाईचारा, सद्भाव या धर्मनिरपेक्षता को सुदृढ़ करने में शून्य योगदान रहा है। संसद पर हमला उनके उप प्रधानमन्त्री व गृहमन्त्री रहते हुआ तो कारगिल में इंटेलीजेन्स फेलियर उनके कार्यकाल की देन है। चौधरी चरण सिंह ताउम्र नीतीश बाबू की तरह दल बदलते रहे। उनके पोते जयन्त चौधरी को एनडीए गठबंधन में शामिल करने, यूपी में किसानों, जाटों के वोटों को भाजपा की झोली में लाने के लिए एक भारत रत्न को कुर्बान किया गया। 6 दिसम्बर 1992 को जब बाबरी मस्जिद ढहायी जा रही थी तो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। यूपी में मुलायम सिंह ने कारसेवकों पर हमले करवाए। उनकी लाशें अयोध्या की सरयू नदी में तैरती मिलीं। पीवी मूकदृष्टा बने रहे। देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बचाने या बनाए रखने में विफल रहे। वे किसी भी मायने में भारत रत्न जैसे सम्मान के पात्र नहीं थे। लेकिन सरकार ने कांग्रेस को चिढ़ाने के लिए उन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया है या फिर बाबरी मस्जिद ध्वंस को चुपचाप सह लेने के लिए और आडवाणी, उमा भारती जैसे नेताओं का मूक साथ देने के लिये? एमएस स्वामिनाथन का योगदान जितना बड़ा है, उसके समक्ष भारत रत्न जैसा पुरस्कार छोटा है। लेकिन यह उन्हें जीते जी कांग्रेस सरकारों की ओर से मिलना चाहिए था। यह पुरस्कार वास्तव में भारत के किसानों का सम्मान है। लेकिन इसे भी राजनीतिक चश्में से देखा जा रहा है। भाजपा इस मु+गालते में है कि स्वामीनाथन को सम्मानित कर देश के करोड़ों किसान आंख मूंद कर ईवीएम पर भगवा कमल बटन उसके पक्ष में दबा देंगे। स्वामीनाथन को दिए जाने वाले भारत रत्न की टाइमिंग को लेकर भी प्रश्न यथावत है। साल 1954 से लेकर 2024 तक कुल 54 भारत रत्न प्रदान किए गए हैं। इनमें से 33 पुरस्कार राजनेताओं की झोली में गए। कांग्रेस भी पुरस्कारों को हथियाने या फिर 'अन्धा बांटे रेवडियां मुड़–मुड़ कर अपनों को ही दे' की कहावत को चरितार्थ करते हुए पीछे नहीं रही। नेहरू, इन्दिरा गान्धी या राजीव गान्धी के परिवारवाद ने भारत रत्न को अपने–अपने सीनों पर शोभायमान किया। नेहरू चीन से हारे, इंदिरा ने आपातकाल घोषित किया और राजीव ने पीएम बनते ही इंदिरा की हत्या के बाद हजारों सिक्खों को मौत के घाट उतार दिया। यानी 62 प्रतिशत भारत रत्न राजनीति को साधने के लिए 'शहीद' कर दिए गए। 18 विभूतियों को राजनीति से इतर जिन पात्र व प्रशंसनीय विभूतियों को यह पुरस्कार दिया गया है, उनमें विनोबा भावे, भूपेन हजारिका, सत्यजीत रे, भीमसेन जोशी, अब्दुल कलाम, बिस्मिला खान, लता मंगेशकर आदि भी शामिल हैं। लेकिन किसी भी भाषा के महान लेखक को भारत रत्न के योग्य नहीं समझा गया। मुंशी प्रेंमचन्द, यशपाल, टैगोर, महाश्वेता देवी या मुलकराज आनंद जैसे बड़े रचनाकारों को यह पुरस्कार मिलना चाहिए था।

विपक्षी दलों के लगभग 200 लोग भाजपा में हुये शामिल

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा जिले में अपना किला और मजबूत करने और मिशन–2024 के दृष्टिगतद्य बुधवार 14 फरवरी को विधानसभा मल्हनी में सदस्यता ग्रहण समारोह आयोजित हुआ जिसमें विपक्षी दलों के लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। भाजपा जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह की संस्तुति के बाद जिला भाजपा कार्यालय पर सपा बसपा और कांग्रेस के लगभग 200 लोग भाजपा में शामिल हुये। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी आमोद सिंह ने बताया कि सदस्यता ग्रहण करने वालों मे जिला पंचायत सदस्य, पूर्व नगर पंचायत सदस्य, प्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीएस सदस्य शामिल हुये। शामिल होने वालों मे अंकुश यादव राजेश कुमार पाण्डेय काशीनाथ सेठ अनिल कुमार चौरसिया श्रीमती नीतू सिंह लाल साहब तिवारी स्वमप्रकाश तिवारी दीनानाथ तिवारी अशोक सिंह अरविन्द सिंह अतुल यादव रजनीश सिंह संदीप कन्नौजिया संजय सिंह साहब लाल यादव जयनेन्द्र सिंह प्रशान्त गौरव सिंह चन्द्रभूषण गौरव सिंह सुनील गुप्ता धीतेष्ट यादव भैयालाल जायसवाल सूर्यबली यादव राजबली यादव प्रतीक सिंह रामआसरे गौतम ऋषिकेश यादव विनोद यादव श्रीमती नेहा सिंह, प्रवीण सिंह मनोज मिश्रा विनोद शर्मा कुमार नट शिवम शर्मा आकाश मौर्य प्रेमप्रकाश, भारती भोले सिंह आलोक मौर्य अजय यादव शिव कुमार विश्वकर्मा पंकज निषाद प्रवीण मिश्रा देवेन्द्र उपाध्याय धीरज गुप्ता रुद्रेश पाठक अरविन्द यादव भोला यादव विकास यादव धर्मवीर सिंह पारसनाथ हरिजन इन्द्रसेन सिंह उमेश सिंह अरविन्द सिंह जितेन्द्र सिंह संजय सिंह जिलेदार गौतम बबलू पासी विकास सिंह लाल बहादुर गौतम टोनी सिंह विनोद सिंह धर्मेन्द्र सिंह आदि थे। उक्त अवसर पर जिला उपाध्यक्ष सुधाकर उपाध्याय संतोष सिंह जिला मंत्री प्रमोद यादव राजू दादा विधानसभा संयोजक प्रबुद्ध दुबे विस्तारक कृष्णा माधव् मंडल अध्यक्ष गण नरेंद्र विश्वकर्मा शैलेश सिंह भूपेश सिंह अजय मिश्रा दिग्विजय सिंह आदि उपस्थित रहे।

'आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा–2023–24 को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई सम्पन्न

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहाँपुर–' जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा–2023–24 के

सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पुलिस के पदों पर भर्ती परीक्षा हेतु तैयारियों को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेट तथा केंद्र व्यवस्थापक के साथ चर्चा की तथा परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश संबधित अधिकारियों को दिये।

आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा–2023–24 दिनांक 17 व 18 फरवरी 2024 को दो–दो पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली में 10.00 बजे से 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली में 3.00 बजे से 05.00 बजे तक जनपद के 11 परीक्षा केन्द्रों पर सम्पन्न करायी जायेगी। सुरक्षा के दृष्टिगत परीक्षा पर कड़े इंतजाम किये गये है। सभी परीक्षा केन्द्रों पर 04 सेक्टर 14 स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किये गये है। जिन परीक्षा केन्द्रों पर अभ्यर्थियों की संख्या 504 से अधिक है उन पर 02 स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गयी है।

जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुये बताया कि जनपद में धारा–144 सीआरपीसी प्रभावी है। परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ एवं अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आईटी०गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा तथा परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में फोटो कॉपियर मशीन संचालित किया जाना तथा परीक्षा केन्द्र के आस–पास 200 मीटर की परिधि के भीतर अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा। उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेट तथा केंद्र व्यवस्थापक को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि उनके द्वारा अपने–अपने परीक्षा केंद्रों पर भ्रमण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि परीक्षा केंद्र पर सभी मूलभूत सुविधाएं एवं सीसीटीवी कैमरे एवं जैमर सुचारू रूप से संचालित हो, यदि कोई भी मूलभूत सुविधा, सीसीटीवी कैमरा एवं जैमर सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा हो तो तत्काल उसको सही कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व समय से स्टेटिक मजिस्ट्रेट एवं परीक्षा कार्य से सम्बद्ध कार्मिकों का परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित समयानुसार प्रत्येक दशा में पहुँचना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के सफल आयोजन हेतु प्रत्येक को संवेदनशील रहकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिये कि परीक्षा केंद्रों पर जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गयी है। केन्द्र व्यवस्थापक उनकी सत्य निष्ठा की पुष्टि अवश्य कर लें। एआरएम रोडवेज तथा एआरटीओं को बसों के संचालन की व्यवस्था तथा निर्धारित किराया सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि होटल अथवा रेस्टोरेंट में रेट लिस्ट अवश्य लगी हो किसी भी चीज की कीमत निर्धारित मूल्य से अधिक न वसूली जाये। सुरक्षा एजेन्सी के प्रतिनिधि को निर्देशित करते हुये कहा कि सुरक्षा संबधी सभी मानको को गंभीरता से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। मोबाइल, बैग इत्यादि जमा करने हेतु क्लॉक रूम परीक्षा कक्ष से दूरी पर बनाये जाने हेतु निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश दिये कि परीक्षार्थी अथवा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी के सिवा कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में प्रवेश न करें यह सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि आयोजित होने वाली परीक्षा में यदि किसी भी अधिकारी की लापरवाही संज्ञान में आती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय कुमार, डीआईओएस हरिवंश कुमार सहित सभी सेक्टरध्स्टेटिक मजिस्ट्रेट एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

केंद्र एवं राज्य सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं से महिलाओं को लाभान्वित किया – सांसद जयप्रकाश रावत

हरदोई (अंबरीष कुमार सक्सेना) आज शक्ति वंदन अभियान का शुभारम्भ भारतीय जनता पार्टी के सांसद जयप्रकाश रावत द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। सांसद जयप्रकाश रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय

नेता है। जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए कन्या सुमंगला योजना चलाई, जननी सुरक्षा योजना चलाई उज्जवला गैस कनेक्शन योजना चलाई और महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया! उन्होंने जनधन खाता खुलवाकर लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में पहुचाने का कार्य किया गया है। तो वहीं उज्जवला योजना के अन्तर्गत गैस कनेक्शन व सिलेण्डर देकर महिलाओं का सम्मान बढाया गया है, आयुष्मान कार्ड योजना से गरीबो का निशुल्क उपचार हो रहा है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर बने इसके लिए दौड़ा के माध्यम से अनेक प्रयास किया जा रहे हैं! भाजपा की सरकार सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास के साथ आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने कहा कि सरकार की योजनाओं से महिलाओं को अनेक प्रकार से लाभ पहुंचाया जा रहा है और आगे भी इसी तरीके से आधी आबादी को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। विधानसभा संयोजक गोपाल त्रिपाठी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम के माध्यम से समाज के लोगों को अनेक लाभदायक योजनाओं से आच्छादित किया है उनका सपना है कि भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति बन उसे सपने को हमारी माता और बहनों को साकार करना है! समापन पर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी आर आर अंबेश ने वंदन शक्ति अभियान में आए हुए अतिथियों एवं माता बहनों का आभार व्यक्त किया।

फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का अधिकारियों ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया

जौनपुर। अमृत योजना के अंतर्गत बने 32 के० एल० डी० क्षमता वाले फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के कार्यक्रम अधिकारी ई० मनीष मिश्रा , नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी पवन कुमार, सफाई निरीक्षक अवधेश कुमार, ट्रांसपोर्ट प्रभारी अनिल कुमार यादव, अमृत योजना से यू आई एस घनश्याम अग्रहरी एवं स्वच्छ भारत अभियान की डी पी एम खुशबू यादव ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। प्लांट में नगर से विभिन्न स्थानों से सेप्टिक टैंको से स्लज ला कर शोधित किया जाना शुरू कर दिया गया है। ई मनीष मिश्रा ने नगर पालिका परिषद जौनपुर में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर सेप्टिक टैंको के सफाई का प्लान तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जिसमें सभी घरों, व्यवसायिक भवनों, सरकारी भवनों, हाउसिंग कॉलोनी , सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय के सेप्टिक टैंको की सफाई के लिए चर्चा की गई। अधिशासी अधिकारी पवन कुमार ने डीस्लजिंग प्लान तैयार कर उसको जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के निर्देश जारी किए। शोधन प्लांट के उचित रख रखाव और सुचारू रूप से संचालन के लिए नगर में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों को नामित करने की योजना बनाई जा रही है। बैठक में एस बी एम और अमृत से खुशबू और घनश्याम ने जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी साझा की।

ठेकेदारों ने अधिक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा'

सुल्तानपुर। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने मंत्री लोक निर्माण विभाग को पत्र लिख कर लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता आरकेसिंह की करी शिकायत ।लोक निर्माण विभाग के पंजीकृत ठेकेदारों ने लगाया आरोप ।ठेकेदारों के कहना है कि अधीक्षण अभियंता सारे कामो में व्याधा उत्पन्न करते है। जैसे समयवृद्धि ,वैरिएशन,अतरिक्त कार्य मद में पैसो की मांग करते है ।इस पैसा न मिलने पर इस हद तक परेशान करते है जिससे कार्य मजबूरी वश रोकना पड जाता है। अधीक्षण अभियंता को इससे कोई फर्क नही पड़ता कि कार्य में देरी हो जाये,कार्य रुक जाए इससे उन्हें कोई मतलब नही रहता ।उनका इस तरह से प्रताड़ित करना कार्यो में देरी की मुख्य वजह बन गया है ।जो भी कागज खण्डीय कार्यालय से उनके पास जाता है ,वो पैसा ना मिलने की वजह से बार बार आपत्ति लगाकर वापस कर देते हैं ।ठेकेदारों के कहना है कि जितने भी अनुबंध गठित है ।वह अधीक्षण अभियंता के वजह से फाइनल नही हो पा रहा ।जिससे प्रत्येक प्रकरण और गंभीर होता जा रहा है ।अधीक्षण अभियंता के इस तरह के चलते ठेकेदार आहत हो कर मंत्री जी को पत्र लिख कर उनके स्थानांतरण करते हुए उनके खिलाफ जांच और कठोर कार्यवाही की मांग समस्त ठेकेदारों ने कर डाली है। इस तरह के अधिकारी अगर विभाग में बैठे हैं तो सरकार की मंशा किस तरह पूर्ण हो पाएगी ।जहां मुख्यमंत्री योगी जी हर कार्य को जनता के लिए जल्द से जल्द पूर्ण करने की बात बार बार करते हैं वही अधिक्षण अभियंता आर के सिंह जैसे अधिकारी अपनी जेब भरने के चक्कर में जनता को समर्पित कार्यो को लटका कर रख रहे हैं ।उन्हें शासन की मंशा से कोई लेना देना ही नही है इस तरह कार्य करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अब ये भी देखना है कि आगे क्या कार्यवाई होती है या सेटिंग गेटिंग के खेल में सफल होते है अधिक्षण अभियंता आर के सिंह ।वहीं आज जिले के समस्त पंजीकृत ठेकेदार लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद से मिलकर करेंगे शिकायत।

'बोर्ड के निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए - एमपी सिंह'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' रसखान प्रेक्षागृह में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा के संबंध में बैठक हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी 17 व 18 फरवरी को आयोजित परीक्षा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां ससमय पूर्ण कर ली जाये। परीक्षा केन्द्र पर प्रकाश सेक्टर मजिस्ट्रेट व स्टेटिक मजिस्ट्रेट परीक्षा केन्द्रों का पूर्व भ्रमण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सभी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी समय से परीक्षा केन्द्र पर पहुचें। प्रवेश के समय परीक्षार्थियों के बायोमेट्रिक की सभी व्यवस्था केन्द्र पर कर ली जाए। परीक्षा केन्द्र पर संदिग्ध निष्ठा व खराब छवि वाले लोगों को तैनात न किया जाए। किसी भी लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारियों का

व शौचालय आदि की उचित व्यवस्था करा ली जाए। पेयजल की उचित व्यवस्था की जाए। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर एक बैनर लगाया जाए व प्रत्येक कक्ष में एक दीवार घड़ी लगवायी जाए। प्रत्येक केन्द्र पर जेनरेटर की व्यवस्था की जाए। केन्द्र पर एक क्लॉक रूम बनवाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट व केन्द्र व्यवस्थापक परीक्षा को शुचितापूर्ण ढंग से सुनिश्चित कराने में अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें। उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। बोर्ड के निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। प्रथम पाली में 9:30 पूर्वान्ह तक परीक्षार्थियों को केन्द्र में प्रवेश दिया जाए। प्रश्न पुस्तिका के पैकेट को दो परीक्षार्थियों के समक्ष खोला जाए। पुलिस अधीक्षक केशव चन्द्र गोस्वामी ने कहा कि केन्द्रों पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा की तैयारियों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने किया बैठक

जौनपुर। आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के सम्बन्ध में तैयारियों की समीक्षा बैठक जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार माँदड़ की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती–2023 की लिखित परीक्षा प्रदेश के समस्त जनपदों में चयनित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गयी है। उन्होंने अवगत कराया गया कि जनपद में 17 व 18 फरवरी को दोनो पालियों (प्रथम पाली प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक, द्वितीय पाली अपरान्ह 03 बजे से 05 बजे तक) परीक्षा सम्पन्न होगी, परीक्षा ड्यूटी में नामित कर्मियों द्वारा परीक्षा केन्द्र पर प्रातः 7 बजे से लेकर सायंकाल की परीक्षा समाप्त होने तक उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। उन्होंने यह भी बताया कि अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रथम पाली की परीक्षा के लिए सुबह 08 बजे तथा द्वितीय पाली के लिए अपरान्ह 01 बजे परीक्षा केन्द्र पर रिपोर्ट करेंगे। जिलाधिकारी ने सेक्टरध्जोनल मजिस्ट्रेट, सभी केन्द्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया कि बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप सभी आवश्यक व्यवस्थाएं ससमय पूर्ण

कर ली जाये। परीक्षा को सुचितापूर्ण एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया जाए। उन्होंने कहा कि केन्द्र व्यवस्थापक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी परीक्षा केन्द्रों के कक्षों में साफ–सफाई, विद्युत व प्रकाश, शौचालय, पेयजल आदि व्यवस्थाएं दुरस्त रहे। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रांरम्भ होने से लेकर ओ0एम0आर0 जमा होने तक सभी व्यवस्थाओं के लिए केन्द्र व्यवस्थापक मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे। केन्द्र व्यवस्थापकों को सहयोग देने के लिए सुरक्षा व अन्य एजेन्सियां कार्य करेंगी। इस दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सभी केन्द्र व्यवस्थापकों को परीक्षा से सम्बन्धित जारी विभिन्न निर्देशों से भी अवगत कराया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉ अजय पाल शर्मा द्वारा भी आवश्यक जानकारी दी। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम अक्षयबर चौहान, अपर पुलिस अधीक्षक द्वय, उपजिलाधिकारी सदर ऋषभ पुंडरीक, जिला विद्यालय निरीक्षक सहित केन्द्रों के व्यवस्थापक आदि उपस्थित रहे।

व्यापार मंडल ने व्यापारियों की समस्या का ज्ञापन सांसद के द्वारा प्रधानमंत्री को भेजा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार के आह्वान पर जौनपुर उद्योग व्यापार मंडल ने व्यापारी समस्याओं को क्रमबद्ध करते हुए एक ज्ञापन जौनपुर लोकसभा सांसद श्री श्याम सिंह यादव के द्वारा प्रधानमंत्री को दिया जिला अध्यक्ष दिनेश टंडन के नेतृत्व में व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को लिखित ज्ञापन जिसमें केंद्र सरकार द्वारा डैडम् लघु एवं शुक्ष्म इकाइयों पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43–बी में किए गए संशोधन को अभिलंब वापस कराए जाने के संदर्भ में तथा UPGST द्वारा वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के वादों की सुनवाई हेतु जारी किए जा रहे नोटिसों और उनमें व्याप्त विसंगतियों का समाधान कराए जाने के संदर्भ में ज्ञापन दिया, जिला अध्यक्ष ने सांसद श्री श्याम सिंह यादव जी को ज्ञापन देते हुए कहा कि उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से व्यापारियों की समस्याओं से संबंधित यह ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाएगा और जल्द ही व्यापारियों की समस्याओं का निवारण होगा, नगर अध्यक्ष राधेरमण जायसवाल ने बताया कि उपयुक्त इस अधिनियम के द्वारा व्यापारियों के साथ अन्याय होगा और यह कानून किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है 45 दिन में अगर कोई व्यापारी जिससे उधारी लिया है उसको चूकता नही करेगा तो वह रुपए उसके आय में जोड़ दी जाएगी, प्रदेश उपाध्यक्ष सोमेश्वर केसरवानी एवं सुभाष अग्रहरि तथा प्रदेश मंत्री महेंद्र सोनकर ने MSME के इस अधिनियम के साथ MSME द्वारा 2017–2018 एवम् 2018–2019 वादों की सुनवाई तथा जारी किए जा रहे नोटिसों को अभिलंब समाधान कराए जाने के संदर्भ में ध्यान आकर्षित करने का निवदेन करते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में इन समस्याओं को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा के आह्वान पर माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा है, प्रतिनिधि मंडल में जिला संरक्षक राजदेव यादव, जिला उपाध्यक्ष अरशद कुरैशी, मुन्ना लाल अग्रहरि, रामकुमार साहू,रमेश बरनवाल,रविंद्र अग्रहरि, हफीज शाह, मनोज कुमार साहू,श्याम चंद्र अग्रहरी, सतीश गुप्ता,अनिल वर्मा, शाहिद मंसूरी,संतोष साहू, इनतेख्वाब आलम, यशवंत साहू आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे प्रतिनिधि मंडल का संचालन नगर अध्यक्ष राधेरमण जायसवाल ने किया उपस्थित सभी पदाधिकारियों का आभार जिला महामंत्री रामकुमार साहू ने व्यक्त किया।

सेंट्रल पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव दिखी संस्कृति की झलक

–धार्मिक एव भारतीय सभ्यता को दर्शाता सेंट्रल पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव।

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। रजनीखण्ड स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव को हर्सोल्लास के साथ मनाया गया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चीफ स्टैंडिंग काउंसिल इलाहाबाद हाई कोर्ट बर काउंसिल के सदस्य प्रशांत सिंह अटल ने शिरकत की भोजपुरी जगत के मशहूर सितारे निसार खान एवं एक्टर राज शर्मा एव पत्रकारिता जगत के एवं समाज एवं पत्रकार की वेलफेयर पर काम करने वाले चर्चित चेहरे राष्ट्रीय जन जंत्री संगठन के अध्यक्ष कमरुल हुदा ने कार्यक्रम में शिरकत की कार्यक्रम का शुभारंभ सुख अतिथि प्रशांत संगठन निसार खान भोजपुरी कलाकार राज शर्मा कमरुल हुदा स्कूल की प्रधानाचार्य दिव्या पांडे संस्थापक जे एन पांडे अध्यक्ष तन पांडे द्वारा दीप प्रचलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया कार्यक्रम की शुरुआत में दीपक प्रकाश,गणेश वंदना,स्वागत नृत्य नृत्य नाटिका – जल बचाओ,

से वार्षिक उत्सव का भविष्य आरंभ हुआ स्कूल की छात्र–छात्राओं द्वारा कई तरह की प्रस्तुतियां दी गई जिसमें नाटक छोटे छोटे तमाशे , फरीज डांस योग प्रदर्शन अभिनंदन समारोह जुम्बा डिस्प्ले मिकी माउस डांस, हाथ ताली नृत्य हनुमान चालीसा, सांकेतिक भाषा में राष्ट्रगान,धन्यवाद ज्ञापन स्कूल कार्यक्रम में

आए छात्र–छात्राओं अतिथियों एवं अभिभावकों ने कार्यक्रम की सराहना की इस अवसर पर प्रशांत सिंह अटल ने बताया कि कार्यक्रम में बच्चों ने हमारी संस्कृत एवं धार्मिक और जल संरक्षण पौधारोपण कई कार्यक्रमों के माध्यम से एक सुंदर सा संदेश दिया है मैं इस कार्यक्रम के लिए स्कूल प्रशासन को आभार व्यक्त करता इस अवसर पर भोजपुरी कलाकार निषाद खान ने कहा कि इस तरह की एक्टिविटी हम सभी ने अपने बचपन में अच्छी है लेकिन आज सेंट्रल पब्लिक स्कूल के इस एनुअल फंक्शन में आकर ऐसा लगा जैसे हमने अपने बचपन को दिया और बच्चों की प्रस्तुतियों से मैं काफी प्रसन्न हूं और स्कूल प्रशासन को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और बच्चों को एक संदेश देने का मौका दिया एक्टर राज शर्मा द्वारा बताया गया की विद्यालय द्वारा वार्षिक उत्सव में तमाम वह प्रस्तुतियां दी गई जिससे एक सुंदर सा संदेश जा सके और बच्चों ने काफी अच्छी एक्टिंग भी की काफी सुंदर प्रस्तुतियां विधि सेंट्रल पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य दिव्या पांडे ने बताया कि स्कूल हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने एनुअल फंक्शन को अलग अंदाज में मना रहा है और हमने और हमारे स्कूल प्रशासन ने प्रयास किया है कि हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता पर हमारे धार्मिक अनुष्ठान को हम किस तरह से दिखा सकते हैं जिसके लिए हमारे विद्यालय प्रशासन हमारे छात्र–छात्र एवं हमारे शिक्षकों ने काफी मेहनत की है ।और आज उसका प्रदर्शन बच्चों ने मंच पर काफी सुंदर अंदाज में किया।

आला अफसर लेते रहे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा, पुलिस की मुस्तैदी के बीच बसंत पंचमी स्नान पर्व सकुशल संपन्न

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। माघ मेला प्रयागराज मीडिया सेल के मुताबिक के प्रयागराज के पावन भूमि पर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के प्राकट्य उत्सव बसंत पंचमी पर आज गंगा,यमुना व अदृश्य सरस्वती के पवित्र पावन संगम में हल्की ठंड हवाओं के मध्य लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगायी। माघ मेला के चतुर्थ स्नान बंसत पंचमी पर श्रद्धालुओं/स्नानार्थियों का संगम की रेती पर जमावड़ा एक दिन पूर्व से ही प्रारम्भ हो गया, संगम स्नान का सिलसिला प्रातः काल शुभ मुहूर्त के साथ प्रारम्भ हुआ जो दिनभर अनवरत जारी रहा। संगम स्नान के उपरान्त श्रद्धालुओंध्स्नानार्थियों ने लेटे हनुमान जी का दर्शन भी किया तथा अक्षय फल की कामना हेतु अन्न, वस्त्र, फल का दान भी किया। स्नानार्थियों में संगम स्नान को लेकर काफी उत्साह देखा गया। इस दौरान श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन व सुरक्षित स्नान हेतु व्यापक पुलिस प्रबन्ध किये गये। श्रद्धालुओं के सुरक्षा के दृष्टिगत सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर नागरिक पुलिस, यातायात पुलिस, घुड़सवार पुलिस, महिला पुलिस, अग्निशमन दल, पीएसी के जवान, एटीएस के कमाण्डों व्यवस्थापित कर सतर्क दृष्टि रखी गई। पवित्र संगम में जल पुलिस के साथ मोटर बोट व गोताखोरध्डीप डाइवर की नियुक्ति कर स्नानार्थियोंध् श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े प्रबन्ध किये गये। इस दौरान स्टीमर के माध्यम से संगम क्षेत्र का लगातार निरीक्षण किया गया एवं एसडीआरएफध्फ्लड कम्पनी के जवानों द्वारा घाटोंध्जल पर लगातार सतर्क दृष्टि रखी गयी। सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे व ड्रोन के माध्यम से चप्पे चप्पे पर नजर रखी गयी।'पब्लिक एड्रेस सिस्टम' के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं से लगातार अनुरोध किया गया कि सावधानी पूर्वक स्नान करें किसी भी संदिग्ध वस्तु को हाथ न लगाये सकुशल स्नान कर अपने गंतव्य को वापस जाएं एवं मेले की सुरक्षा व स्वच्छता में हमारा सहयोग करे, मेले में आने वाले स्नानार्थियों/श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो इसके दृष्टिगत मेला क्षेत्र में ही 06 स्थानों पर 'पार्किग' की समुचित व्यवस्था की गयी। जिसके माध्यम से यह प्रयास किया गया कि संगम में आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान घाट तक पहुचने में न्यूनतम पैदल चलना पड़े। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज रमित शर्मा ध्, मंडलायुक्त प्रयागराज विजय विश्वास पंत ध्, पुलिस उप महानिरीक्षकध्प्रभारी माघ मेला डॉ राजीव नारायण मिश्र ध्, लगातार मेला क्षेत्र में ही रहकर सभी व्यवस्थाये सुनिश्चित कराते रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घुड़सवारी के माध्यम से भी संगम क्षेत्र का भ्रमणध्निरीक्षण किया गया। प्रभारी माघ मेला डॉ0 राजीव नारायण मिश्र ध् द्वारा ड्यूटी पर तैनात समस्त पुलिस कर्मियों की कुशलता ली गयी तथा उनका उत्साहवर्धन किया गया व कमाण्ड सेन्टर के माध्यम से लगातार मेला क्षेत्र में सतर्क दृष्टि रखी गयी। पुलिस कर्मियों में मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था के साथ–साथ व्यवहार में भी सेवा का भाव दिखाई पड़ा व सकुशल व सुरक्षित स्नान सम्पन्न कराने हेतु पुलिस के आला अफसर लगातार मेला क्षेत्र में डटे रहें, तथा उच्चाधिकारियों द्वारा मेला क्षेत्र में आये हुये स्नानार्थियोंध् श्रद्धालुओं से लगातार उनका कुशलक्षेम पुछा गया। स्नान के बाद लोगो ने प्रसिद्ध मंदिरों का दर्शन कर मेले में लगी प्रदर्शनी का भी लुत्फ उठाया। मेला क्षेत्र में नव निर्मित खोया पाया केन्द्रों के माध्यम से भूले भटकों को उनके परिजनों से मिलाया गया स्नानार्थियों में धर्म आस्था के प्रति काफी उत्साह देखने को पाया गया तथा मेले की व्यवस्था देखकर देश के कोने–कोने से आये श्रद्धालुओं ने अत्यन्त प्रसन्नता व्यक्त की। पुलिस बल के अथक प्रयासों के फल स्वरूप बसंत पंचमी का यह स्नान पर्व भी शान्ति और सुगमता के साथ सकुशल सम्पन्न हुआ,जिसकी उच्चाधिकारियों द्वारा प्रशंसा की गयी।

जमीन की पैमाइश मामले में छः हजार घूस लेते लेखपाल गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। जमीन की पैमाइश मामले में विजिलेंस की टीम ने शिकायत कर्ता की शिकायत पर मंगलवार को रुदौली तहसील में तैनात लेखपाल शिव कुमार पांडेय को 6 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। विजिलेंस टीम ने लेखपाल के खिलाफ रूदौली थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। बताते चलें कि लेखपाल शिवकुमार पांडेय ने रेहरा बड़ागावं निवासी नीलाम्बर यादव से जमीन की पैमाइश को लेकर 6 हजार रुपयों की मांग की थी। जिसके बाद नीलांबर ने मामले की शिकायत विजिलेंस विभाग में की थी।लेखपाल को गिरफ्तार करने वाली विजिलेंस टीम की ट्रैप टीम प्रभारी अजय प्रताप सिंह, निरीक्षक विद्या शंकर पांडेय, ध्रुव चद मौर्या, राम पाल सिंह, उपनिरीक्षक राज बहादुर यादव, मुख्य आरक्षी राघवेन्द्र, विनोद, अरविंद पांडेय शामिल रहे।

मां-बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, एक ही बेड पर मिले शव

अयोध्या। जिले में दो अलग–अलग घटनाओं मां–बेटे समेत तीन लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है।पहली घटना जिले के बीकापुर के भावापुर गांव में हुई। जहां 75 वर्षीय मां और 32 वर्षीय बेटे की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों बीमार चल रहे थे।वही दूसरी अन्य घटना खंडासा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमानीगंज में हुई। इसमें कमरे में सफाई कर्मी बिस्तर पर मृत पाया गया। सफाई कर्मी संतोष कुमार थाना इनायतन नगर के तरौली गांव का रहने वाला था। इन घटना से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी पुलिस जांच कर रही है।थाना खण्डासा क्षेत्र के पीएचसी अमानीगंज में सफाई कर्मी उम्र लगभग 45 साल का शव कमरे के अन्दर आज सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में बिस्तर पर पाया गया। पीएचसी में तैनात सफाई कर्मी दिलिप कुमार जब सुबह करीब सात बजे उसे जगाने उसके कमरे पर गया तो आवाज देने पर संतोष कुमार नहीं उठा। उसको हिलाया–डुलाया तब भी कुछ असर नहीं हुआ। दिलीप कुमार ने घटना की जानकारी सीएचसी अधीक्षक खंडासा को दी। अधीक्षक ने पीएचसी पहुंचकर मामले की जानकारी थानाध्यक्ष खण्डासा मनोज यादव को दी। उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचकर मृतक सफाई कर्मचारी संतोष कुमार पुत्र राम खेलावन निवासी तरौली बाजार थाना कोतवाली इनायत नगर के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कराने के पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया।

यातायात नियम का करे पालन चालक - आरटीओ प्रवर्तन

सड़क सुरक्षा की अनदेखी हादसे का कारण – एआरटीओ प्रवर्तन

अयोध्या। वाहन चालक वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करते समय वाहन चलाये।आपका जीवन आपके परिवार के लिए काफी अमूल्य है। इसलिए वाहन चलाते समय उतनी ही गति रखे जितने मे वाहन आपके नियंत्रण में हो।यह बातें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन पर सम्भागीय कार्यालय में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) विश्वजीत प्रताप सिंह ने कही। इस मौके पर उन्होंने सभी चालकों से अपील किया कि जब वे सभी अपने अपने घर से निकलते हैं तो उनके वापस लौटने का इंतजार उनके परिजनों के सभी सदस्यों को रहता है। इसलिए आप के सलामत से घर वापस आने का आपके परिवार के लोगों को काफी बेसब्री से इंतजार रहता है।कार्यक्रम का संचालन डॉ० आर०पी० सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अयोध्या द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि अधिकतर

दुर्घटनायें मुख्यतः सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी एवं सड़कों की इंजीनियरिंग के कारण होती है।ऑकड़ों के अनुसार 34 प्रतिशत दुर्घटनायें राष्ट्रीय राजमार्ग एवं 29 प्रतिशत दुर्घटनायें राजकीय मार्ग एवं शेष दुर्घटनायें अन्य मार्गों पर होती हैं।उन्होंने बताया कि सड़क पर चलते समय दो पहिया वाहन चालक/पीछे बैठने वाले हेलमेट अवश्य लगायें तथा चार पहिया वाहन चालक सेफ्टी बेल्ट का उपयोग अवश्य करें जो दुर्घटना होने पर जोखिम की मात्रा को कम करते हैं। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए एवं नशे की हालत में वाहन नहीं चलाना चाहिए।सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) श्री सिंह द्वारा सभी उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ भी दिलायी गयी एवं उपस्थित जनों को धन्यवाद देते हुए सड़क सुरक्षा के नियमों के अनुपालन हेतु जागरूक किया गया। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) प्रवीण कुमार सिंह के अतिरिक्त कार्यालय के सभी कर्मचारीगण एवं अन्य आगन्तुकगण मौजूद रहे।

एंटी करप्शन टीम ने एक वर्ष में कसा कई घूसखोर कर्मियों पर शिकंजा

एंटी करप्शन टीम को घूसखोर कर्मियों की सूचना – राय साहब द्विवेदी

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। भ्रष्टाचार निवारण संगठन अयोध्या रेंज में तैनात प्रभारी निरीक्षक राय साहब द्विवेदी के नेतृत्व में टीमों ने रेंज के पांचों जिले के अलग अलग तहसीलों से एक साल के अंदर एक दर्जन से अधिक घूस लेते हुए घूसखोर कर्मचारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर जेल भेजने का सराहनीय कार्य किया।गिरफ्तार किए घूसखोरों में लेखपाल,भू राजस्व निरीक्षक, पेशकार चकबंदी विभाग में तैनात लेखपाल,एडीओ पंचायत, कनिष्ठ लिपिक सहित अन्य सरकारी कर्मचारी शामिल रहे। इस संबंध में भ्रष्टाचार निवारण संगठन अयोध्या रेंज में प्रभारी निरीक्षक राय साहब द्विवेदी ने बताया कि पिछले वर्ष फरवरी माह से अब तक विभाग ने भ्रष्टाचार मामले में लिप्त 13 भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक घूसखोर कर्मी अयोध्या जिले से तथा सबसे कम गोंडा,अमेठी व सुल्तानपुर जिले से रंगे हाथों दबोचे गए। उन्होंने बताया कि अयोध्या जिले के रौनाही थाना क्षेत्र से लेखपाल दिनेश कुमार, गोंडा जिले के तरबगंज में कार्यरत पेशकार संतोष राव, सुल्तानपुर जिले के लंभुआ तहसील में लेखपाल पद पर कार्यरत विकास सिंह, अयोध्या जिले के मिल्कीपुर तहसील में कार्यरत बृजेश सिंह,मवई विकास खण्ड में तैनात एडीओ पंचायत रवीन्द्र, अमेठी जिले में लेखपाल पद पर कार्यरत दुर्गा प्रसाद मिश्र, विकास भवन अयोध्या में कनिष्ठ लिपिक पद पर कार्यरत आनंद विक्रम उपाध्याय को घूस लेते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसी तरह सदर अयोध्या में चकबंदी लेखपाल पद पर कार्यरत विकास कुमार, सुल्तानपुर जिले के कुड़वार तहसील में कानूनगो व उनके मुंशी कुलदीप तिवारी, अकबरपुर तहसील में कार्यरत व लेखपाल संघ अध्यक्ष लेखपाल रुपेश यादव, सुल्तानपुर जिले के कादीपुर तहसील में कानूनगो पद कार्यरत राजित राम शर्मा, चकबंदी आफिस में अयोध्या में चकबंदी लेखपाल पद पर तैनात राम नारायण, बीकापुर जिले में लेखपाल पद पर कार्यरत विंध्या प्रसाद तिवारी, अम्बेडकर नगर जिले के जलालपुर में लेखपाल पद पर तैनात राम यश को घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ कर जेल भेजा। उन्होंने बताया कि घूस लेने वाले भ्रष्टाचारियों में सबसे अधिक कर्मी राजस्व विभाग से जुड़े हुए हैं और सबसे अधिक गिरफ्तारी अयोध्या जिले से हुई है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि अगर आपसे सही काम को करने के लिये कोई भी सरकारी अराजपत्रित अधिकारी व कर्मचारी घूस मांगने का कार्य करता है तो आप बेहिचक हमारे मोबाइल नंबर 9454401900 पर सूचना दे सकते हैं।आपका नाम व पहचान गोपनीय रखा जायेगा।

गोमती नदी में मछली पकड़ते समय दो लोग डूबे – पुलिस ने एक युवक का शव किया बरामद, दूसरे की तलाश जारी

अयोध्या। मिल्कीपुर में गोमती नदी में मछली पकड़ने आए दो लोग डूब गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी।जिसके बाद पुलिस ने दोनों की छानबीन की। जिसमें एक युवक का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। जबकि दूसरे युवक की तलाश जारी है। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना कुमारगंज क्षेत्र फाजलपुर गांव निवासी राम किशोर पुत्र सजाऊ गांव के ही राममिलन पुत्र राम आनंद के साथ गांव के पास से गुजरी गोमती नदी में रविवार की शाम करीब 6रू00 बजे मछली का शिकार करने के लिए इदिलपुर घाट पर गए थे। काफी रात बीतने के बाद जब वापस नहीं आए तो परिजन खोजते हुए घाट पर पहुंचे और आवाज लगाई लेकिन कोई पता नहीं लग सका। परिजनों के कहने पर ग्रामीण जब उस नाव की खोज करने लगे जिस नाव से दोनों लोग शिकार कर रहे थे। तो वह नाव रात करीब 8 बजे सथिन पुल के पास मिली नाव में मोबाइल व जल भी रखा हुआ था। जिसके बाद ग्रामीणों ने शंका व्यक्त किया की नदी में ही डूब गए है। पूरी रात लोग खोजबीन करते रहे जब कहीं पर कोई पता नहीं लग सका तो परिजनों ने घटना की जानकारी सुबह पुलिस चौकी प्रभारी देवगांव अभिषेक त्रिपाठी को दी।मौके पर पुलिस टीम के साथ पहुंचे चौकी प्रभारी ने घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को देते हुए स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोपहर बाद राममिलन का शव नदी से बरामद कर लिया। प्रभारी निरीक्षक रतन सिंह ने बताया कि राम मिलन का शव नदी से बरामद हो गया है। पोस्टमार्टम को भेजने के लिए विधिक कार्रवाई की जा रही है। तथा दूसरे व्यक्ति राम किशोर निषाद पुत्र सजाऊ की तलाश गोताखोरों से कराई जा रही है। मृतक राम मिलन अपनी बहन रोशनी की शादी भी ठान रखी थी जो मई में होनी थी उससे पहले ही मौत हो गई। राममिलन की 3 वर्ष की बेटी आशिकी रो रही है और पूछ रही है कि मम्मी पापा कब आएंगे।

एलपीसीपीएस के नाम रही जीनियम इण्टरनेशनल की ट्राफी'

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, विनम्र खंड, गोमती नगर का तीन दिवसीय वार्षिकोत्सव 'जीनियम इण्टरनेशनल 6.0' का समापन मंगलवार को हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात फैशन डिजाइनर आसमां हुसैन और विशिष्ट अतिथि डॉ नलिना सिंह, एमिटी विश्वविद्यालय ने विजयी प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की। 126 अंकों के साथ जीनियम इण्टरनेशनल की ट्राफी लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज (एलपीसीपीएस) के नाम रही।

कार्यक्रम में संस्था के महाप्रबंधक एवं पूर्व विधान परिषद सदस्य डॉ. एसपी सिंह, मुख्य प्रसाशिका एवं पूर्व एमएलसी कांति सिंह, निदेशिका गरिमा सिंह, शिखर पाल सिंह, प्रतापगढ़ सदर के पूर्व विधायक नागेन्द्र यादव, पारसनाथ यादव, रमेश यादव, संस्थान के डीन प्रो. लक्ष्मी शंकर अवस्थी समेत सभी शिक्षक उपस्थित रहे।

तीन दिन तक चलने वाले जीनियम इण्टरनेशनल में करीब 100 कॉलेज और विश्वविद्यालयों के दो हजार छात्र–छात्राओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें नुक्कड़ नाटक, नृत्य, गायन आदि सहित 42 विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चों ने प्रतिभाग लिया। इस इण्टरनेशनल फेस्ट में 18 देशों के 40 से अधिक बच्चों ने भी हिस्सा लिया।

श्री लंका, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, नमीबिया, कंबोडिया, मॉरीसस, युगाण्डा, तंजानिया, केन्या, यूथोपिया, अंगोला, नाइजीरिया, गाम्बिया और इराक आदि देशों के प्रतिभागी जीनियम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में दो लाख आठ हजार रुपये के चेक भेंट किये गए। साथ ही 448 प्रतिभागियों को मेडल्स और 104 प्रतिभागियों को ट्राफी प्रदान की गई।

रफ्तार का कहर ट्रक में घुसी एम्बुलेंस

–ट्रक में घुसी एम्बुलेंस ,चालक समेत दो घायल।

सुल्तानपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हुई दुर्घटना।राजधानी लखनऊ से लौट रही एम्बुलेंस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर दुर्घटना ग्रस्त हो गयी। आज 14 फरवरी को माइल स्टोन 136 पर एम्बुलेंस नम्बर यूपी 32 जी 6338 जिसका चालक कृष्णकांत निवासी ग्राम सुरूरपुर थाना दोस्तपुर जिला सुल्तानपुर चला रहा था। गाड़ी में सहायक मुकेश भी बैठा था। एम्बुलेंस लखनऊ से आजमगढ़ की ओर जा रही थी पर पीछे से एक ट्रक में टकरा गई। एंबुलेंस में बैठे दोनों व्यक्तियों की चोट लगी है। घटना के बाद दूसरे एंबुलेंस द्वारा अंबेडकर नगर इलाज के लिए ले जाया गया। मौके पर यूपीडा पेट्रोलिंग स्टाफ ने आवागमन चालू करवाया।

श्वान साशा ने पलक झपकते ही खोजा विस्फोटक

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। एआईपीडीएम बैठक के दूसरे दिन, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कंप्यूटर जागरूकता प्रतियोगिता जिसे कंप्यूटर लैब, यूपी पुलिस हेडक्वार्टर्स में आयोजित किया गया। इसे एआईपीडीएम, परीक्षा पोर्टल और ब्रीफिंग्स पर प्रस्तुतियों के साथ शुरू किया गया। हरियाणा टीम की निकासी के बावजूद, सभी 70 शेष प्रतिभागियों ने परीक्षा में भाग लिया। बीएसएफ के गगन चौधरी विजेता बने, जबकि हिमाचल प्रदेश पुलिस से अमन कुमार और आईटीबीपी से आनंद शंकर ने दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। समयानुसार, श्वानदस्ता प्रतिगोतिया जो की 3BN/RPSF में शुरू हुई, इसमें 42 श्वान दस्तों ने ट्रैकिंग कार्यक्रम में भाग लिया, जिन्हें कर्नल सुरेंद्र सैनी, लेफ्टिनेंट कर्नल राज भारत (एनएसजी) और लेफ्टिनेंट कर्नल विनसन आरवीसी ने समीक्षा की। इसके बाद, नारकोटिक्स और विस्फोटक प्रतियोगिताएँ शुरू हो गई, जिसमें नारकोटिक्स में 29 कर्मचारी और विस्फोटक में 45 प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ प्रदर्शन किया। ट्रैकिंग कार्यक्रम में, अधिकांश लक्ष्यों (25 में से 22) को असम राइफल्स के साशा (श्वान) ने पहचाना। एंटी सबोटाज चेक प्रतियोगिता में दो आयोजन होते हैंरू जेआर आरपीएफ अकादमी के मुख्य हॉल में ग्राउंड सर्च का लिखित परीक्षण और अकादमी के पीटी मैदान में व्यक्तिगत टीमों के लिए प्रैक्टिकल प्रदर्शन किया जाता है। जिसने हिमाचल प्रदेश टीम ने भाग नहीं लिया। एक्सेस

कंट्रोल प्रतियोगिता के विजेता निम्नलिखित थेः पहले अनिल कुमार सिंह (आईटीबीपी), दूसरे खादर शरीफ शेख (तेलंगाना पुलिस), और तीसरे स्थान पर बराबरी के साथ स्वप्निल दरावड़े (महाराष्ट्र पुलिस) और कमल चेत्री (असम राइफल्स)। जेआर आरपीएफ अकादमी हॉल में, वैज्ञानिक सहायता और जांच आयोग में फोरेंसिक साइंस टेस्ट शामिल था, जिसके बाद एक अवलोकन टेस्ट हुआ और फिर पुलिस पोर्ट्रेट टेस्ट हुआ, जिसमें सभी प्रतिभागियों को एक पोर्ट्रेट दिखाया गया और उन्हें उसे पुनः बनाने के लिए कहा गया।

आज अपराध सीन फोटोग्राफी वैज्ञानिक जांच आयोग का आयोजन किया गया, जिसमें कुल भागीदारी 58 की है, जिसमें से 55 ने भाग लिया, 1 को अयोग्य ठहराया गया और 2 रद्द किए गए हैं।

लोनी चीनी मिल पहुंचे स्टेट बैंक के अधिकारियों ने किसानों की समस्याएं सुनकर किया समाधान

हरदोई (अंबरीष कुमार सक्सेना) डीसीएम श्रीराम लिमिटेड शुगर यूनिट लोनी प्रांगण में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बृहद कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें एसबीआई के सहा.महाप्रबंधक कृषि व्यवसाय इकाई लखनऊ विपिन सिंह और मुख्य प्रबंधक केपी शर्मा खास अतिथियो के रूप में यहां पहुंचे। डीसीएम श्री राम शुगर मिल के इकाई प्रमुख राजा श्रीवास्तव ने क्षेत्र में मिल द्वारा किए जा रहे सामाजिक एवं आर्थिक विकास से जुड़े प्रयासों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया वर्तमान पेराई सत्र में कुल 125 लाख कुंतल गन्ने की पेराई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सत्र 2022–23 में कुल 403.05 करोड़ रूपये का गन्ना मूल्य भुगतान कृषकों के बैंक खातों में किया जा चुका है जिसमें सबसे अधिक रुपया 92.51 करोड़ का भुगतान भा.स्टेट बैंक के माध्यम से किया गया। बताया चीनी मिल के लगभग 10 हजार किसान एसबीआई की विभिन्न शाखाओं से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आगामी पेराई सत्र 2024–25 से चीनी मिल के हो रहे विस्तारी करण से संबंधित जानकारी देते हुए किसानों से कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने और अधिक उपज प्राप्त कर लाभान्वित होने की अपील अपील करते हुए एसबीआई द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी देकर आने वाले बैंक के आला अफसरों का आभार व्यक्त किया। लखनऊ से पधारे बैंक के सहा.महाप्रबंधक विपिन सिंह ने मौजूद कृषकों को बैंक द्वारा चलाई जा रही किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि समृद्धि ऋण योजना, गोल्ड लोन, ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्रों से संबंधित ऋण योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने शिविर में आने वाले सभी कृषको की छोटी बड़ी समस्याओं को सुना और उनका उचित समाधान भी बताया। लेखा विभाग के विभागाध्यक्ष बीपी शर्मा द्वारा सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त कर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस मौके पर 200 से अधिक इलाकाई किसानों के साथ–साथ एसबीआई हरदोई के मुख्य प्रबंधक संजीव कुमार, शाहबाद शाखा प्रबंधक सुशील कुमार वर्मा, चीनी मिल के गन्ना विभाग की केन मैनेजर अली आरजू जैदी, गौरव रस्तोगी समेत मिल के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

इक्यावन किलो की माला पहनाकर लोक निर्माण मंत्री का किया गया स्वागत

सुल्तानपुर। जिला पहुंचने पर लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद का हुआ भव्य स्वागत। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने 51 किलो की माला पहनाकर मंत्री का किया स्वागत अभिनंदन। कादीपुर में विधायक राजेश गौतम की उपस्थिति में करेंगे 80 सड़कों का शिलान्यास और 91 सड़कों का लोकार्पण। प्रशासन की निगरानी में मंत्री के कार्यक्रम की व्यापक तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9628325542, 9415034002

RNI सन्दर्भ संख्या – 24/234/2019/R/-1

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।